शिक्षा के निजीकरण का कांग्रेस ने किया विरोध

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जुलाई. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने और उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

बुधवार को कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी. उमंग सिंघार ने कहा कि देशभर के छात्र बेरोजगारी, परीक्षा पत्र लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, छात्रावासों की बदहाल स्थिति और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों की आवाज को दबाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे सरकारी उच्च शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी, जबकि सरकारी विश्वविद्यालय पहले से ही शिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं.

उमंग सिंघार ने कहा कि भर्ती में लगातार हो रही देरी, उच्च शिक्षा पर सीमित सरकारी खर्च और सरकारी छात्रावासों की खामियों जैसे मुद्दों को कांग्रेस विधानसभा के भीतर और जनता के बीच लगातार उठाती रहेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

निजी विवि संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का हमला

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सरकार पर उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विधेयक का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन प्रदेश में उच्च शिक्षा के मानकों को गिराने के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को भी संकट में डाल सकते हैं. महेश परमार ने कहा कि वर्ष 2007 के मूल अधिनियम में निजी विश्वविद्यालयों के लिए 25 एकड़ परिसर, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु पांच करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि तथा 2,500 वर्गमीटर के प्रशासनिक भवन जैसी अनिवार्य शर्तें थीं. संशोधन में इन्हें हटाकर 'पर्याप्त भूमि' और 'पर्याप्त भवन' जैसे अस्पष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के साथ भी विश्वविद्यालय संचालित किए जा सकेंगे. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शिथिल नियमों के कारण छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गई थी.

ई-उर्वरक वितरण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की मुहर

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश में लागू ई-विकास (डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सप्लाई सॉल्यूशन सिस्टम) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और गैर-कृषि उपयोग रोकने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय है, जिसमें न्यायालय सीमित परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है. दायर याचिका में कहा गया था कि ई-टोकन प्रणाली लागू होने से इंटरनेट और तकनीकी जानकारी के अभाव में किसानों और उर्वरक विक्रेताओं को परेशानी हो रही है.

भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

CS TECH Ai Enhancing Possibilities

साएन्सिस टेक लिमिटेड (CS TECH Ai) द्वारा मध्य प्रदेश में

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (बीएलसी घटक)

को लागु करने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

सभी पद प्रारंभिक ३६ माह की अवधि के लिए पूर्णतः संविदा के आधार पर होंगे।

*आपके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के अधीन।

पद	पदों की संख्या	कार्यस्थल	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव
सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी	1	भोपाल	भू-अभिलेख एवं भूमि संबंधी अनुमतियों में न्यूनतम 20 वर्षों का गहन अनुभव।
परियोजना प्रबंधक	1	भोपाल	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव।
संभागीय प्रबंधक	10	प्रत्येक संभागीय मुख्यालय	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा संबंधित क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव।
वरिष्ठ एमआईएस (MIS) विशेषज्ञ	13	प्रत्येक संभागीय मुख्यालय	कंप्यूटर साइंस/आईटी/एमसीए में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा डेटा प्रबंधन में 8 वर्षों का अनुभव।
कनिष्ठ सिविल इंजीनियर	80	संपूर्ण मध्य प्रदेश	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. अथवा डिप्लोमा तथा 5 वर्षों का अनुभव।
कनिष्ठ एमआईएस (MIS) विशेषज्ञ	110	संपूर्ण मध्य प्रदेश	कंप्यूटर साइंस/आईटी/कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्नातक अथवा डिप्लोमा, 3 वर्षों का अनुभव तथा डेटा प्रबंधन कौशल।

कृपया QR कोड के माध्यम से Google Forms अवश्य भरें तथा अपना रिज़्यूमे, प्रशंसापत्र एवं आवश्यक दस्तावेज pmay@cstech.ai पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए www.cstech.ai पर जाएँ।

एक नजर में

व्यापक कार्रवाई से वसूला 10 लाख का राजस्व

सिंगरौली. जिले में ओवरलोडिंग, खुले में सामग्री परिवहन और परिवहन नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जहां विशेष जांच अभियान चलाते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की. इस अभियान के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक का शासकीय राजस्व भी वसूल किया गया. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम ने मटवई एनटीपीसी तथा चौकी निवास स्थित जेपी प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश वाहनों की विशेष जांच की.

उर्वरक बिक्री में गड़बड़ी 38,850 की हेराफेरी

पांढुर्ना. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने पांढुर्ना के तत्कालीन गोदाम प्रभारी एवं क्षेत्र सहायक मनोज कुमार टेपे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं. जांच में सामने आया कि उन्होंने 16 जून से 2 जुलाई 2026 के बीच 118 किसानों को एमओपी उर्वरक निर्धारित ?1,800 प्रति बोरी के बजाय ?1,975 में बेचकर ?38,850 की अतिरिक्त राशि वसूली, जिसे संघ के खाते में जमा नहीं किया. जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित अवधि के उर्वरक विक्रय के **बिल या कैश मेमो जारी नहीं किए गए.

मानसून ने मध्यप्रदेश में की दमदार वापसी

15 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

भोपाल, 22 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया और किसानों के साथ आम लोगों को भी राहत मिली है.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताते हुए बुधवार को 15 जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडौरी जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. वहीं श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार और बड़वानी में भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया सहित कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं. बारिश की वापसी का असर प्रदेश के वर्षा आंकड़ों पर भी दिखाई देने लगा है. सोमवार तक प्रदेश में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन मंगलवार तक यह कमी घटकर 14 प्रतिशत रह गई.

> अब तक प्रदेश में औसतन 286.8 मिलीमीटर (11.3 इंच) वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस समय तक 335.3 मिलीमीटर (13.2 इंच) बारिश सामान्य मानी जाती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में अब भी 18 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 11 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है. हालांकि ताजा बारिश के बावजूद प्रदेश के 41 जिलों में अब भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है. दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, सीहोर, देवास, हरदा, उज्जैन, राजगढ़, नीमच, खंडवा और खरगोन सहित 14 जिलों में बारिश का प्रदर्शन सामान्य से बेहतर रहा है.

टेंपल बांड के तहत बनेगा बगलामुखी लोक

- नलखेड़ा जाएंगे सिंहस्थ मेला अधिकारी
- माता का लेंगे आशीर्वाद, 31 जुलाई तक पूरी करना है प्रक्रिया

नव भारत न्यूज

उज्जैन. महाकुंभ-2028 की तैयारियों के बीच धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई टेंपल बॉन्ड योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है. इसीकक्रम में गुरुवार को संभाग आयुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह आगर-मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी माता मंदिर, नलखेड़ा का दौरा करेंगे.

यहां वे मंदिर परिसर का अवलोकन कर टेंपल बॉन्ड योजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। 31 जुलाई तक योजना की प्रक्रिया पूरी करने के लक्ष्य को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

आकार लेगा बगलामुखी लोक -प्रशासन का उद्देश्य बगलामुखी धाम को भविष्य में 'बगलामुखी लोक' के रूप में विकसित करना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं. माना जा रहा है कि महाकाल लोक की तर्ज पर यदि यह योजना साकार होती है तो नलखेड़ा देश के प्रमुख शक्तिपीठों में और अधिक आकर्षण का केंद्र बनेगा.

कैसे होता है संचालन देखेंगे

दैनिक नवभारत से चर्चा में आशीष सिंह ने बताया कि नलखेड़ा प्रवास के दौरान मंदिर ट्रस्ट, पुजारियों, कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी. मंदिर की वर्तमान पूजन व्यवस्था, प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, पार्किंग, प्रसाद एवं पूजन सामग्री की दुकानों, यात्री सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा. इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि टेंपल बॉन्ड योजना के तहत यहां कौन-कौन से विकास कार्य, सौंदर्यीकरण, विस्तार और आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं.

टेंपल बांड से बड़े बदलाव -महाकुंभ-2028 की तैयारियों के तहत लागू की जा रही टेंपल बॉन्ड योजना को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. योजना के माध्यम से मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकेंगी.

1100 करोड़ की स्कीम,200 करोड़ बांड से जुटेंगे

1100 करोड़ रुपये की इस व्यापक कार्ययोजना के लिए तीन स्तरों पर वित्तीय व्यवस्था की गई है. इसमें 200 करोड़ रुपये टेंपल बॉन्ड के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जिनकी अवधि 10 वर्ष होगी. इसके अलावा 275 करोड़ रुपये अर्बन चैलेंज फंड से तथा 625 करोड़ रुपये विभिन्न बैंकों से वित्तीय सहयोग के रूप में प्राप्त किए जाएंगे.

यह सारे मंदिर शामिल

योजना के अंतर्गत उज्जैन संभाग के 11 प्रमुख धार्मिक स्थलों का चरणबद्ध विकास किया जाएगा. इनमें कालभैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम, नवग्रह शनि मंदिर, 84 महादेव मंदिर श्रृंखला, अंगारेश्वर महादेव मंदिर, भूखी माता मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, सिद्धवट तथा आगर-मालवा का बगलामुखी माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख देवस्थान शामिल हैं. इन सभी मंदिरों में सौंदर्यीकरण, पार्किंग, विश्राम गृह, सुगम दर्शन व्यवस्था, पेयजल, यात्री सुविधाएं, कतार प्रबंधन और आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाएगा.

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी जरूरी

भोपाल, 22 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थी देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं और लोकतंत्र को समझकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना ही जागरूक नागरिक की पहचान है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, कानून निर्माण और संसदीय परंपराओं को समझने का सर्वोत्तम विद्यालय है. मुख्यमंत्री विधानसभा के समिति कक्ष में आगर-मालवा और जबलपुर से आए मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे. विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने पहुंचे आगर-मालवा के 50 से अधिक तथा स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल, जबलपुर के 40 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए. विद्यार्थियों ने बताया कि पहली बार विधानसभा की कार्यवाही को निकट से देखने का अवसर उन्हें प्रेरणादायी लगा. मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिभा, नवाचार और सृजनशीलता की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

इस अवसर पर आगर विधायक माधव सिंह (मधु गहलोत) और जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहाणी के मार्गदर्शन में आए विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से तैयार मॉडल और आकर्षक सीनरी भी भेंट की.

हर विधानसभा में खुलेगी कृषि यंत्र किराये की दुकान

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक 'कृषि यंत्र किराये की दुकान' खोली जाएगी. कृषक कल्याण वर्ष-2026 के तहत इस पहल का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम शुल्क पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है. वर्तमान में प्रदेश में 5,260 कृषि यंत्र किराया केंद्र संचालित हैं, जबकि हर वर्ष 1,060 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे. प्रदेश कृषि यंत्र निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है. विदिशा कृषि उपकरण निर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां करीब 150 निर्माण इकाइयों में ग्रेडर, लेवलर, हाइड्रोलिक ट्रॉली, कल्टीवेटर और प्लाऊ जैसे उपकरण बनाए जा रहे हैं.

उच्च स्तरीय समिति गठित करे सरकार

नई दिल्ली, 22 जुलाई .अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जंतर-मंतर पर नीट-यूजी समेत विभिन्न शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और अराजकता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों का समाधान संवाद, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों के माध्यम से होना चाहिए, न कि हिंसक टकराव से. अभाविप ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ वह शुरू से विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही है. परिषद ने भारत सरकार से मांग की है कि परीक्षा प्रणाली की शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए,

विधानसभा में फिर गूंजेगा सीधी के अवैध प्लाटिंग का मामला!

- डिंडोरी विधायक ने प्रदेश में अवैध प्लाटिंग को लेकर लगाया है प्रश्न
- सीधी के अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर भी करेंगे चर्चा

आदित्य सिंह

सीधी 21 जुलाई. विधानसभा में फिर से सीधी के अवैध प्लाटिंग का मामला गूंजेगा. डिंडोरी विधायक ने प्रदेश में अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रश्न लगाया है। सीधी के अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर भी चर्चा करेंगे.

प्रदेश विधानसभा में डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम द्वारा अवैध प्लाटिंग को लेकर तारांकित प्रश्न क्रमांक 1431 लगाकर जानकारी मांगी गई है. उनके प्रश्न के जवाब के लिये कलेक्टर सीधी को भी संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर से पत्र क्रमांक 21205, दिनांक 3 जुलाई 2026 भेजा गया है. जिस पर सीधी से भी जवाब प्रेषित किया जा चुका है. दरअसल सीधी जिला मुख्यालय में ही अवैध कालोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं. ऐसी कालोनियों में अपनी जमा पूंजा लगाने वालों को न तो मापदंड के अनुसार चौड़ी व्यवस्थित सडकें मिलेती हैं और न ही गंदे जल निकासी के लिये नाली व विद्युत सुविधा नजदीक में मिलती है. आने वाले समय में अवैध प्लाटिंग के चलते सीधी बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा. बताते चलें कि अवैध कालोनियों पर विगत वर्ष प्रदेश के नगरीय एवं विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 23 जुलाई 2024 को समीक्षा बैठक में अधिकारियों का सख्त निर्देशित किया गया था कि प्रदेश में अवैध कालोनियों पर तत्काल रोक लगे और दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. विडम्बना यह है कि सीधी में उक्त आदेश पर धरातल में कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, लिहाजा अवैध कालोनियों की बसाहट का काम तेजी के साथ चल रहा है.

आधा दर्जन से अधिक शिकायत की नपा ने भेजी जानकारी-नगरपालिका सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिंडोरी विधायक द्वारा अवैध प्लाटिंग की जानकारी हेतु लगाए गए प्रश्न के जबाब में नपा सीधी द्वारा नगर पालिका परिषद सीधी में अवैध प्लाटिंग से संबंधित शिकायतकर्ता बृजेश नाथ शास्त्री एवं माधवेश तिवारी द्वारा की गई आधा दर्जन से अधिक शिकायतों की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को भेजी गई है.

सीधी विधायक भी विधानसभा में उठा चुकी हैं मामला -सीधी विधायक रीती पाठक विधानसभा में सीधी के अवैध प्लाटिंग के काले कारोबार का मामला उठा चुकी हैं. सीधी विधायक द्वारा उठाये गये मामले पर विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था. जिला मुख्यालय में इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है. रेरा नियमों के विपरीत अब भी अवैध प्लाटिंग पूंजीपतियों द्वारा करके बेची जा रही है. अवैध प्लाटिंग के बाद लोगों को फंसाने के लिये दलालों का सहारा लिया जाता है.

इनका कहना है....सीधी में अवैध कालोनियों का मामला संज्ञान में आया है. जनमानस के हितों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं. सीधी के अवैध प्लाटिंग पर प्रमुखता से विधानसभा में जवाब मांगा जायेगा. **-ओमकार सिंह मरकाम, विधायक डिंडोरी**

नवभारत ने प्रमुखता से उठाया था मामला

सीधी में अवैध प्लाटिंग के चल रहे काले कारोबार के मामले को नवभारत द्वारा प्राथमिकता के साथ उठाया गया था. इसका असर यह है कि सीधी विधायक द्वारा भी अवैध प्लाटिंग के मामले को प्राथमिकता से लिया गया और विधानसभा में उठाने के साथ जिला स्तर पर भी संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के लिये जोर दिया जा रहा है.

कार्रवाई : सीएचओ को सेवा से पृथक करने का प्रस्ताव

धार, 22 जुलाई. जिले में सरकारी कार्यालय में बैठकर केंद्र सरकार और उसके समर्थकों पर टिप्पणी करने तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियो बनाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने उन्हें सेवा से पृथक किए जाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), भोपाल के मिशन संचालक को भेजा है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाग विकासखंड के काकड़वा गांव में पदस्थ सीएचओ किरण भाटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में अपनी टिप्पणी की थी.

पेज एक का शेष

विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट से बैकफुट पर सरकार

जब तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल सुधार नहीं किए जाते. हालांकि चौतरफा घिरती और बढ़ते जन-आक्रोश से दबाव में आई सरकार के रुख में अब एक कूटनीतिक बदलाव साफ नजर आ रहा है. सरकार अब केवल सख्त रुख अपनाने के बजाय सक्रिय संवाद की रणनीति पर उतर आई है. छात्रों और वांगचुक से संपर्क साधना इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि असंतोष के सुलगते मोर्चों को शांत किया जा सके और विपक्ष के हाथों से बड़े मुद्दे छीने जा सकें. इतना ही नहीं संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने का बयान भी यह दिखाता है कि सरकार अब विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट से बैकफुट पर है.

कांग्रेस ने फूलों से किया भाजपा का स्वागत

कांग्रेस ने पूछा—पेपर लीक पर क्या है रुख?

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जुलाई . प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बुधवार को उस समय राजनीतिक माहौल अलग ही नजर आया, जब पूर्व मंत्री डॉ. मुकेश नायक के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाथों में फूल लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध मार्च का इंतजार करते दिखाई दिए. कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक कटुता के बीच सद्भाव का संदेश बताया.

पत्रकारों से चर्चा में डॉ. मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस 'मोहब्बत की दुकान' की राजनीति में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र में संवाद और सौहार्द भी उतना ही आवश्यक है. इसी भावना के साथ भाजपा नेताओं का फूलों से स्वागत करने की तैयारी की गई थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से एक अहम सवाल पूछना चाहती थी कि क्या वह लगातार सामने आ रहे परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों का समर्थन करती है. उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल को अपना स्पष्ट रुख जनता के सामने रखना चाहिए.

बस पलटी, छह से सात यात्रियों को मामूली चोटें

भिण्ड. जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-719 पर गोहद के निकट बुधवार सुबह एक निजी यात्री बस के पलट जाने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि छह से सात अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी आना माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार ग्वालियर से सुबह लगभग 5.30 बजे एक निजी बस भिण्ड होते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन के लिए रवाना हुई थी. बारहेड़ से आगे गोहद की ओर जाते समय चालक को कथित रूप से झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. उस समय बस में लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे.

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E-mail:- gmmp@fci.gov.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2026/25 दिनांक : 23.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है ।

किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा। **महाप्रबंधक (क्षेत्र)**

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60